उद्योग और विकास के लिए खुला खजाना

1000 करोड़ रुपये शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए

लखनऊ। योगी सरकार 2.0 के दूसरे बजट में औद्योगिक नीतियों, कुशल युवा और अवस्थापना संबंधी विकास के लिए मुक्त हाथों से धन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में एफडीआई के साथ ही फॉर्च्यून कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पांच अन्य नीतियों के लिए भी धन का आवंटन किया गया है। अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्राक्चर मिशन के लिए भी 400 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

सरकार ने उप्र इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण व गतिशीलता नीति-2022 के तहत ईवी निर्माण, चार्जिंग सुविधाएं के लिए टोकन मनी के रूप में बजट खोल दिया गया है। एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उप्र आक्सीजन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय मदद के लिए 67.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में सब्सिडी के लिए बजट में एक लाख रुपये की टोकन व्यवस्था के साथ इसका रास्ता खोल दिया गया है। सेमी कंडक्टर

20 करोड़ रुपये की व्यवस्था भूमि पूजन समारोह के लिए की गई है

नीति के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन के बाद अब औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है।

मोटो जीपी कार्यक्रम इस साल भी, 10 करोड़ मिलेंगे : देश में पिछली बार पहली बार यूपी में मोटो जीपी का आयोजन कराया गया था। इस वर्ष भी ग्रेटर नोएडा में इसका भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो